Tc.No.: GUJHIN00722

दैनिक

क्रांति समय

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 61, मंगलवार, 27 मार्च 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

सार समाचार

पत्रकार से बदसलूकी मामले में महिला पुलिसकर्मी सहित दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

26 मार्च को पत्रकार पुलिस मुख्यालय पर जताएंगे रोष

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरोजनी नगर इलाके में जेएनयू छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला फोटो जर्नलिस्ट से बदसलूकी और उससे कैमरा छीनने का मामला तूल पकड़ने पर गुस्साए पत्रकारों के पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन के बाद उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर पत्रकारों को शांत कराया और सतर्कता विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच में पीड़ित महिला पत्रकार से हाथापाई व जबरन कैमरा छिनने के मामले में दोषी पाए गए एक हेड कांस्टेबल व डीएपी की एक महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार 26 मार्च को पत्रकारों ने एक बार फिर पुलिस मुख्यालय के पास बड़ी तादाद में एकत्र होकर रोष जताने का निर्णय लिया। पत्रकारों का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर हरबार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने पर कुछ छोटे पुलिसकर्मियों पर गाज गिरती है और कभी किसी बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती।

सामूहिक विवाह समारोह संपन्ननई दिल्ली (एसएनबी)। समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति की ओर यमुना बाजार कथा कुंज में राम नवमी के दिन 9 कन्याओं का सामूहित विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर समिति के प्रधान संजय गर्ग व उप प्रधान संजय वर्मा ने कहा कि चयनित जोड़े निर्धन परिवार के है, जिनकी आर्थिक स्थित बेहद कमजोर है। साल भर पहले इन युवक युवतियों को समिति ने अपनी देखरेख में विवाह के लिए पंजीकृत किया था। विवाह के बाद अर्थिक रूप से कमजोर इन जोड़ों को गृहस्थ जीवन के निर्वाह के लिए 21 सामान उपहार के रूप में भेंट किए गए। विवाह के बाद वधु को स्वालम्बी बनने के लिए समीति ने सिलाई मशीन प्रदान की।

दुर्घटना मामले में आरोपी की जेल की सजा बरकरार

नई दिल्ली (एजेंसी)। लापरवाही से अपनी कार चलाते हुए दो लोगों को जख्मी करने के दोषी एक व्यक्ति के प्रति नरमी बरतने से इनकार करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने एक महीने की जेल की सजा को बरकरार रखा और कहा कि आग से खेलने वाला व्यक्ति झुलसने की शिकायत नहीं कर सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के गुप्ता ने व्यक्ति को एक महीने की सजा प्रदान करने के मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में इस तरह की सजा जरूरी है ताकि वाहन चलाने वाले लोगों के दिमाग में यह बात रहे कि उन्हें गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। अदालत ने अपनी दोषसिद्धि और एक महीने की सजा को चुनौती देने वाले गुरविंदर सिंह की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने उसकी अपील ठुकराते हुए कहा कि दोषी दक्षिण दिल्ली में ओखला-लाजपत नगर के निकट सड़क पर जल्दबाजी में ट्रैफिक सिग्नल पार कर रहा था और उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिस पर दो लोग सवार थे। सुनवाई के दौरान आरोपी ने आरोपों से इंकार किया था और कहा था कि यह पीड़ितों की गलती थी।

दलितों के उत्थान के लिए सरकार संकल्पबद्धः तिवारी

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से गिहारा समाज: उत्थान विषयक विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने क हा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति समाज और कमजोर वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका विकास अभियान से हर वह व्यक्ति लाभांवित हो रहा है चाहे वह सुदूर राज्य के गांव में रह रहा है या फिर महानगर में। सरकार सभी नागरिको को एन नजर से देख रही है। प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मोहन लाल गिहारा ने गिहारा समाज के उत्थान की बात की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समाज और कमजोर वर्गों की पूर्ववर्ती की सरकारों द्वारा पूर्णत: उपेक्षा होती रही है। इन्हें कांग्रेस और अन्य दलों ने केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया और इनके कल्याण के लिए कोई भी सार्थक काम नहीं किये हैं। आज अनुसूचित जाति समाज और कमजोर वर्गों के लोग पूरी तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर विास कर रहे हैं।

350 रुपये का लालच देकर जुटाई गई केजरीवाल की रैली में भीड़!

नई दिल्ली। हरियाणा के हिसार में रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और दिल्ली जैसा जादू फिर दोहराया जाएगा। इस दौरान इस रैली में अच्छी भीड़ भी जुटी थी। इसी भीड़ को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें कुछ लोग खुद को इसी रैली में मौजूद भीड़ का हिस्सा बता रहे हैं और साथ ही यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें रैली में शामिल होने के लिए 350 रुपये और खाना दिए जाने का वादा किया गया था। लेकिन रैली खत्म होने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं दिए हैं।

साथ ही वीडियो में दिख रहा शख्स खुद को दिहाड़ी मजदूर बता रहा है और कुछ महिलाओं को भी इसी तरह का लालच देकर इस रैली में शामिल करने की बात कह रहा है। इन आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल के विरोधियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि जो राजनीति बदलने आए थे, वे खुद बदल गए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हिसार के पुराना कॉलेज ग्रांउड से मिशन 2019 की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में दंगे करवाने वाली पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाए कि बीजेपी और कांग्रेस ने वोट की राजनीति के लिए हरियाणा में जाटों और गैर जाटों के बीच दंगे करवाए हैं।

चाकू से गोद कर युवक की हत्या

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही पूछताछ हत्या की कोशिश के एक मामले कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था युवकरंजिश के चलते हत्या की आशंका केएन काटजू इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक का नाम महेन्द्र सिंह उर्फ सोनू है। पुलिस ने उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावरों से बचने की कोशिश में भाग रहे युवक का पीछा कर बदमाशों ने उस पर चाकू ताबड़तोड़ कई वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के वक्त युवक अपनी पत्नी के लिए मोमोज लेने बाइक पर बाजार के लिए निकला था। मृतक के परिजनों ने पांच युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या का केस दर्ज कर पुलिस बताए गए बदमाशों में से एक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण आपसी रंजिश हो सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महेन्द्र कुछ दिन पहले ही हत्या की कोशिश के एक मामले में जमानत पर जेल से छूटा था। जांच-पड़ताल में पता चला कि महेंद्र सिंह उर्फ सोनू (27) सपरिवार रोहिणी सेक्टर-16 में रहता था और पेशे से चालक था। शनिवार रात सवा आठ बजे पुलिस को सूचना मिली थी की रोहिणी सेक्टर-16, गली नंबर-3 के पास एक युवक को पीट-पीट कर घायल कर दिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने मन्नू, काला, रवि, हैप्पी और कृष्ण नामक पांच युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है।

>>>> यूपी : आजमगढ़ में दो एटीएम हैकर गिरफ्तार,

पेशे से इंजीनियर ये हैकर इस तरह चुराते थे पैसे

आजमगढ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से पुलिस ने दो एटीएम हैकरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पेशे से इंजीनियर थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अजय कुमार सिंह व विक्रांत सिंह को कोतवाली इलाके से रविवार रात गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी लिपि डाटा सिस्टम्स में इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे। आरोपियों ने पुलिस को अपने अन्य दो साथियों-सद्दाम व अशोक प्रजापति के बारे में भी जानकारी दी। ये दोनों अभी भी आजाद घूम रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि जब इन अपराधियों को एटीएम में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के लिए बुलाया जाता था तो ये अपने साथ एक हार्ड डिस्क लेकर आते थे, जिस पर पहले से ही एक सॉफ्टवेयर अपलोड होता था। हार्ड डिस्क का इस्तेमाल एटीएम के ढक्कन को खोलने के लिए एक आम कुंजी बनाने के लिए किया जाता है। यह हार्ड डिस्क कंपनी द्वारा

इन्हें दी गई थी। मशीन के खुलने के बाद वे उसमें रखे पैसे चुरा लेते थे। हार्डडिस्क में छेड़छाड़ करने वाले एटीएम इंजीनियर गिरफ्तार इसकी जानकारी एटीएम संरक्षक को नहीं हो सकती। सिर्फ इंजीनियर इसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा वे एटीएम में लगाए गए सीसीटीवी को बंद कर देते थे और पहले से सेव डाटा को भी डिलीट कर देते थे। आरोपियों ने वाराणसी, जौनपुर व आजमगढ़ जिलों में अपराध करने की बात कबूली है। वे कम से कम छह मामलों में शामिल रहे हैं, जिनमें 15 लाख रुपये से ज्यादा की चोरी की गई।

>>>> 5 परियोजनाओं की रखी नींव

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे काशी,

वाराणसी (एजेंसी)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को काशी पहुंचे। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद की काशी में यह पहली यात्रा है। राष्ट्रपति ने आज यहां बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी साढ़े तीन हजार करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित 10 युवाओं को विभिन्न कंपनियों की ओर से नियुक्ति पत्र भी सौंपे। वह साढ़े आठ घंटे काशी में गुजारेंगे।

राष्ट्रपति कोविन्द ने NHAI की जिन परियोजनाओं का श्रीगणेश किया गया है वे वाराणसी और आस-पास के क्षेत्र की यातायात सुविधा को मजबूत एवं सुगम बनाएंगी। इससे, यहां के सभी निवासियों का जीवन अधिक सुविधा-जनक हो सकेगा, साथ ही विकास के नए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि 'नेशनल वाटर वे – वन', 'ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर' तथा NHAI के राजमार्गों के माध्यम से वाराणसी, भारत के उत्तरी राज्यों के लिए, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार बन गया है। 'नेशनल वाटरवे - वन' गंगा-जल-मार्ग के जरिये वाराणसी को इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक के व्यापारिक केन्द्रों से जोड़ेगा। इस वाटरवे पर पटना और वाराणसी के बीच क्रूज

वेसेल्स चलाने का काम शुरू कर दिया गया है।

स्प्रिच्युअल सिटी से स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रही काशी: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा कि भारत सरकार गंगा-नदी की स्वच्छता और उसके तटों पर बसे क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। वाराणसी में 'नमामि गंगे' परियोजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम शुरू हो गया है और साथ ही घाटों के सुधार आदि का कार्य भी प्रगति पर है। सफाई के कारण अब गंगा-नदी के घाटों की सुंदरता दिखने लगी है। यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जन-भागीदारी से ही संभव हो सका है। मैं इस सराहनीय कार्य के लिए वाराणसी की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि वाराणसी का हस्त-शिल्प बहुत ही कलात्मक, और लोकप्रिय रहा है। बनारसी साड़ी और कालीन बनाने वालों का हुनर मशहूर है। हस्त-शिल्पियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पादों को बाज़ार से जोड़ने के लिए अनेक प्रकल्प चलाए गए हैं।

लगभग एक लाख बुनकर भाइयों और बहनों को सुविधाएं देने का लक्ष्य है। यह हस्त-कला संकुल वाराणसी क्षेत्र के कारीगरों को सुविधा प्रदान करने, उनकी आमदनी बढ़ाने और नए रोजगार पैदा करने में सहायक होगा।

संस्कृति-सभ्यता के साथ व्यापार व विकास की धाराओं को भी प्रवाहित करती रही है गंगा

राष्ट्रपति ने कहा कि वाराणसी को आर्थिक विकास की धुरी बनाने के लिए यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का तेजी से विकास किया जा रहा है। यहां बन रहे मल्टी-मोडल टर्मिनल के पास एक फ्रेट विलेज विकसित करने की योजना है। इससे सड़क, रेल और जल-मार्ग के जरिए सामान ले जाना सुविधाजनक हो सकेगा।

राष्ट्रपति कोविन्द ने प्राचीन काल से ही वाराणसी शहर गंगा नदी पर विकसित जलमार्गों तथा सड़क परिवहन के जरिये उत्तर भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता रहा है। गंगा नदी, संस्कृति और सभ्यता के साथ-साथ, व्यापार और विकास की धाराओं को भी प्रवाहित करती रही है। इस मौके पर सूबे के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। राष्ट्रपति कोविंद सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल राम नाईक व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा मेयर मृदुला जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष अपराजिता सोनकर ने किया। यहां से राष्ट्रपति वायुसेना के हेलीकाप्टर से 11.35 बजे बड़ालालपुर हैलीपैड पहुंचे। यहां से कार से दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कार्यक्र में शिरकत की।

अगले तीन साल में देंगे 50 लाख युवाओं को नौकरीः मुख्यमंत्री

वाराणसी (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अगले तीन वर्षों में 50 लाख युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार देने जा रहे हैं। इसमें केवल 4 लाख सरकारी नौकरियां हैं। इसके अलावा 1.62 हजार नियुक्तियां केवल पुलिस विभाग में की जाएंगी। सोमवार को बड़लालपुर में आयोजित राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शिरकत पहुंचे मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा उनकी नीति-नियति दोनों गलत होने के कारण कई सरकारी विभागों में नौकरियों का रास्ता बाधित था। हमाकई अन्य विभागों की नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही उन विभागों में भी नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 व 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश हुई इन्वेस्टर्स मीट के बाद 4 लाख 68 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे। उनमें से 25 हजार करोड़ के काम के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। इनके भूमिपूजन का कार्य शीघ्र ही किया जाएगा।

संस्कृत को जनमानस की भाषा बनाने की जरूरतः सिसोदिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संस्कृत को जन उपयोगी और जन मानस की भाषा बनाने की आवश्यकता है। अब तक संस्कृत के बारे में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में यही भाव है कि यह एक ऐसा विषय है जिसे पढ़कर अच्छे नंबर लाने हैं जिससे ओवरआल परसेंटेज अच्छा रहे। इस भाव से हमें संस्कृत को बाहर निकालना है। सिसोदिया दिल्ली में तीन दिवसीय अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे,जिसका आयोजन दिल्ली संस्कृत अकादमी की ओर से किया जा रहा है। सिसोदिया ने कहा कि किसी भाषा की समृद्धि का इस बात से पता नहीं चलता कि उसे कितने लोग बोलते हैं बल्कि इस बात से पता चलता है कि वह भाषा साहित्य और विज्ञान के मामले में कितनी समृद्ध है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ''शिक्षित राष्ट्र - समर्थ राष्ट्र'' के नारे पर काम कर रही है,लेकिन जब शिक्षा की बात होगी तो शिक्षा संस्कृत के बिना अधूरी ही रहेगी। वहीं दिल्ली संस्कृत अकादमी के सचिव जीतराम भट्ट ने बताया कि दिल्ली सरकार दिल्ली स्टेट संस्कृत एजुकेशनल काउंसिल गठित करने जा रही है।

तोहफाः प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने को मुफ्त जमीन मिलेगी

लखनऊ (एजेंसी)। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कम आय वर्ग के लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का और सरलीकरण किया जा रहा है। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को इस योजना में कांशीराम योजना की तर्ज पर नजूल की जमीन मुफ्त में दी जाएगी। आवास विभाग इस संबंध में जल्द ही संशोधित शासनादेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने इस योजना के आधार पर शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना में दो लाख रुपये में दो कमरे का मकान देने की योजना शुरू की है। इस योजना में मकान बनेंगे साढ़े चार लाख रुपये में, लेकिन इसमें ढाई लाख रुपये सब्सिडी दी जाएगी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने इस योजना में पहले साल एक लाख मकान देने का लक्ष्य विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को दिया था, लेकिन जमीन न मिलने की वजह से योजना परवान नहीं चढ़ सकी। आवास विभाग में हाल ही में विकास प्राधिकरण के

उपाध्यक्षों और आवास विकास परिषद के आयुक्त की बैठक हुई थी। इसमें शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले मकानों के प्रगति के बारे में जानकारी मांगी गई। अधिकतर अधिकारियों ने मकान के लिए जमीन न होने की जानकारी दी। अधिकारियों ने इसके साथ ही यह तर्क रखा कि इस योजना में मकान बनाने का लक्ष्य पाने के लिए कांशीराम आवास योजना की तर्ज पर जमीन की व्यवस्था की जाए। सूत्रों का कहना है कि इसी के आधार पर शासन स्तर पर तय किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को नजूल की जमीनें मुफ्त में दी जाएंगी। आवास विभाग इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने वाला है।

दखल

उपचुनाव पर भारी राज्यसभा की सफलता

संख्याबल के लिहाज से भाजपा राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और कुछ क्षेत्रीय दलों की मदद से आसानी से बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। ऐसे में अब भाजपा के सामने उच्च सदन से किसी बिल को पास कराने के लिए पहले जैसी टेंशन नहीं रही। भाजपा और बहुमत के बीच का यह फासला और घटेगा क्योंकि तीन मनोनीत सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इनकी जगह नए लोग मनोनीत होंगे।

23 मार्च को संसद की 26 राज्यसभा सीटों के लिए सात प्रदेशों की राज्य विधानसभाओं में चुनाव हुए। वास्तव में राज्यसभा के लिए कुल 17 राज्यों में चुनाव हुए थे। इनमें से 10 राज्यों के 33 प्रत्याशियों को तो निर्विरोध चुन लिया गया और शेष सात राज्यों- उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, केरल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से सामान्य प्रक्रिया द्वारा सदस्य चुने जाने थे। इन 17 राज्यों के 58 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल-मई में समाप्त हो रहा है। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रतिनिधि राज्य है। सात राज्यों में से अकेले उत्तरप्रदेश से 10, पश्चिम बंगाल से पांच, कर्नाटक से चार, झारखंड से दो, केरल से एक, तेलंगाना से तीन व छत्तीसगढ़ से एक सीट निर्धारित है। उत्तरप्रदेश में नौ सीटों पर भाजपा व एक पर सपा, पश्चिम बंगाल में तीन पर तृणमूल व एक पर कांग्रेस, कर्नाटक में तीन पर कांग्रेस व एक पर भाजपा, झारखंड में एक पर भाजपा, एक पर कांग्रेस, केरल में एक पर जेडीयू तथा तेलंगाना में सभी तीन सीटों पर सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति को विजय मिली।

अभी राज्यसभा में भाजपा के 58 सांसद हैं, जिनमें से 14 सांसद अप्रैल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अप्रैल के बाद उसके मात्र 44 सांसद होते लेकिन इस चुनाव के बाद उसके 28 और सांसद हो गए। इस तरह उसकी राज्यसभा सांसदों की संख्या 72 हो गई, जिसमें से 17 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। इसके बाद भाजपा सदन में सबसे बड़ा दल हो गया है। 1980 में पार्टी के गठन के बाद यानी 38 वर्षों की राजनीतिक यात्रा में वह पहली बार राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। राष्ट्र संचालन के शीर्ष प्रशासनिक अंग राज्यसभा सदन में भाजपा सांसदों का संख्याबल सबसे अधिक होना अद्वितीय उपलब्धि है, लेकिन 245 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिए अनिवार्य 126 संख्या बल तक पहुंचने के लिए भाजपा को अभी कुछ और वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। 2014 तक राज्यसभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत व कांग्रेस शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की ही राज्यसभा सदस्य के रूप में अधिक गिनती थी, जो 2014 के बाद भाजपा द्वारा विभिन्न राज्यों में बहुमत से चुनाव जीतने पर कम होती रही। लेकिन इस बार अकेले उत्तरप्रदेश से भाजपा नौ सीटें (एक भाजपा समर्थित सपा अनिल अग्रवाल की सीट) जीती है। बाकी पांच प्रदेशों से उसे कुल तीन सीटें और मिलीं।

उत्तरप्रदेश ऐसा प्रदेश है जो केंद्रीय सत्ता के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में हमेशा प्रमुख भूमिका में होता है। पांच राज्यों में से उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनावों में ऐसे ही समीकरणों को बनते-बिगड़ते देखा गया। जिस राजनीतिक उद्देश्य से गोरखपुर, फूलपुर लोकसभा सीट पर उप-चुनाव के लिए सपा-बसपा का गठबंधन हुआ था, वह राज्यसभा चुनाव में बसपा के एक भी सांसद के न चुने जाने से ध्वस्त हो गया है। 403 विधायकों वाले उत्तरप्रदेश में भाजपा के पास 324 विधायक हैं। बहरहाल, उत्तरप्रदेश से राज्यसभा के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। इस गणना के अनुसार, एक राज्यसभा प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए 37 विधायकों के मत की आवश्यकता होती है। भाजपा के 324 विधायकों के अनुसार उसकी 8 राज्यसभा सीटें तो पहले ही सुनिश्चित थीं। आठ राज्यसभा सदस्यों को चुनने के बाद भी 324 में से उसके 28 विधायक बचते थे। यह संभावना पहले ही थी कि यदि भाजपा को विपक्षी दलों या निर्दलीय दलों के किन्हीं 9 और विधायकों का साथ मिले तो 9वीं राज्यसभा सीट भी उसी की होगी और अंतिम चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसा हुआ भी। 403 में से 400 विधायकों ने मतदान किया था। सपा के हरिओम यादव व बसपा के मुख्तार अंसारी के जेल में बंद होने के कारण चुनाव आयोग ने उनके मतदान पर रोक लगा दी थी, जबकि बिजनौर से भाजपा विधायक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद खाली पड़ी सीट की मतगणना नहीं हो सकी। उन्नाव जिला स्थित पुरवा क्षेत्र के बसपा विधायक अनिल सिंह ने अप्रत्याशित रूप में भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर बसपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बसपा का राज्यसभा की सीट के बिना रह जाना भाजपा और उसके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी तरफ यूपी में सपा के 47 विधायक हैं। 37 विधायकों के समर्थन वाली एक सीट उसकी सुनिश्चित थी, जिस पर उसने जया बच्चन को चुन लिया था। इसी बात से नाराज होकर नरेश अग्रवाल पिछले दिनों सपा छोड़ भाजपा में शामिल हो गए।

उप-चुनाव से पूर्व जिस तरह सपा-बसपा का राजनीतिक गठबंधन तैयार हुआ तथा कांग्रेस ने जिस तरह इसे राजनीतिक समर्थन दिया, उससे लगने लगा था कि बसपा उप-चुनाव में अपने प्रत्याशी इसीलिए नहीं उतार रही क्योंकि उसे राज्यसभा में अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है और इसके लिए उसे राज्यसभा चुनाव आते-आते सपा, कांग्रेस, रालोद व दो निर्दलीय विधायकों की सहायता से अपना प्रत्याशी उतारने का अवसर भी मिल गया था। लेकिन क्या पता था कि बसपा विधायक अनिल सिंह राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करके बसपा को झटका दे देंगे। यह राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और परम विचारणीय अवसर है कि इस बार उत्तर प्रदेश से कांग्रेस व बसपा का एक भी सदस्य राज्यसभा के लिए नहीं चुना गया है। गोरखपुर, फूलपुर व अररिया लोकसभा सीटों पर भाजपा की पराजय के बाद उपजी उसकी हताशा व रोष में अवश्य ही यूपी के राज्यसभा चुनाव के बाद कमी हुई होगी। बहरहाल, यूपी समेत सात राज्यों में राज्यसभा की 25 सीटों में 12 सीटें जीत भाजपा ने देश के उच्च सदन में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। संख्याबल के लिहाज से भाजपा राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और कुछ क्षेत्रीय दलों की मदद से आसानी से बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। ऐसे में अब भाजपा के सामने उच्च सदन से किसी बिल को पास कराने के लिए पहले जैसी टेंशन नहीं रही।

भाजपा और बहुमत के बीच का यह फासला और घटेगा क्योंकि तीन मनोनीत सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इनकी जगह नए लोग मनोनीत होंगे। ऐसे में मोदी सरकार के लिए गैर-एनडीए और गैर-यूपीए दलों से मुद्दे पर आधारित समर्थन हासिल करना आसान होगा। निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद मोदी सरकार के लिए अपने मनचाहे बिलों को पास कराने में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोकसभा में भाजपा अकेले दम पर बहुमत में है। एनडीए के सहयोगियों के साथ 540 सदस्यीय लोकसभा में इसकी सदस्य संख्या 315 है। परिणाम आने के बाद साफ हो गया है कि एनडीए को अगर एआईएडीएमके, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी जैसी पार्टियों का समर्थन मिल जाता है तो बहुमत के आंकड़े यानी 123 को हासिल करना कठिन नहीं होगा। हालांकि वर्ष 2019 में ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की प्रतिद्वंद्वी है लेकिन पार्टी पहले के कुछ मौकों पर केंद्र सरकार को नीतिगत समर्थन देती आई है।

हालांकि आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि अभी राज्यसभा में 115 सदस्यों (यूपीए, लेफ्ट और तृणमूल) की तरफ से सरकार को कड़ी चुनौती मिलती रहने वाली है। सरकार के पास तीन सदस्यों के कार्यकाल खत्म होने पर नए सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। माना जा रहा है कि ये तीन सदस्य भी सरकार का ही समर्थन करेंगे। निर्दलीय सदस्यों के भी सरकार के साथ ही आने की संभावना है। सरकार अहम मुद्दे पर अपने पूर्व सहयोगी इंडियन नेशनल लोकदल से भी बात कर सकती है जिसके पास राज्यसभा की एक सीट है।

विकेश कुमार बडोला
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

राज-विचार

गन संस्कृति से पीछा छुड़ाए अमेरिका

अमेरिका में फ्लोरिडा के स्कूल में 40 दिन पहले हुई फायरिंग में 17 बच्चों की मौत के बाद गन कंट्रोल की मांग को लेकर ऐतिहासिक मार्च निकाले गए। अमेरिका में यह बदलाव बेहद जरूरी है। आए दिन स्कूलों और सड़कों पर हो रही गोलीबारी चिंता पैदा करने वाली है।

अमेरिका में फ्लोरिडा के स्कूल में 40 दिन पहले हुई फायरिंग में 17 बच्चों की मौत के बाद गन कंट्रोल की मांग को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन ऐतिहासिक मार्च में बदल गए। वॉशिंगटन में अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मार्च निकला। इसमें पांच लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इससे ज्यादा लोग सिर्फ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की शपथ में जुटे थे। वॉशिंगटन के अलावा पूरे अमेरिका में 700 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए। ब्रिटेन में लंदन, जापान के टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, भारत में मुंबई समेत दुनिया के 100 शहरों में गन कंट्रोल की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। तीन साल पहले ऑरेगॉन के कॉलेज में नौ लोगों की हत्या के बाद उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा रो तक पड़े थे। अमेरिकी कांग्रेस के 70 फीसदी सांसद हथियारों की समर्थक थे। लिहाजा ओबामा बेबस रहे। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते महीने फ्लोरिडा स्कूल में गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात में कहा था- फायरिंग की घटनाओं से निपटने के लिए हर टीचर के हाथ में पिस्टल थमा देंगे।

गन कंट्रोल की मांग के बीच अमेरिका की स्थिति देखें, तो गन इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ की है। अमेरिका में गन कल्चर की वजह आर्म लॉबी है, जो पॉलिसी प्रभावित करती है। 51 साल में गोलीबारी में 15 लाख जानें गईं। 2018 में स्कूलों में 20 बार फायरिंग हुई। 9/11 के बाद गोलीबारी की 400 से ज्यादा घटनाएं हुई और स्कूल ज्यादा निशाना बने। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में बंदूक की संस्कृति कभी इतनी वीभत्स होगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं रहा होगा। ऐसी सोच कहां से पैदा हुई तो शक की सुई अमेरिकी बंदूक की संस्कृति पर ही जाती है। यह मुद्दा अमेरिकी राजनीति में अहम अमेरिका में कई दशकों से गंभीर बहस चल रही है, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो पाया है। सवाल है कि बंदूक की संस्कृति का संरक्षक कौन है? 5 दिसंबर 1791 को अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन में बंदूक रखने को बुनियादी अधिकार माना गया है।

गौरतलब है कि अमेरिका की दुनिया की आबादी में 4.4 फीसद हिस्सेदारी है, लेकिन करीब 42 प्रतिशत अमेरिकी लाइसेंसी हथियार रखते हैं। 88.8 फीसद अमेरीकियों के पास बंदूकें हैं, जो दुनिया में प्रति व्यक्ति बंदूकों की संख्या के लिहाज से बड़ा आंकड़ा है। यही वजह है कि प्रति 10 लाख आबादी पर सरेआम गोली चलाने (मास शूटिंग) की घटनाएं अमेरिका में सबसे ज्यादा होती हैं। मुश्किल यह है कि अमेरिका के हर राज्य का अपना कानून है, इसलिए इस मसले पर जब तक राजनीतिक गलियारे में व्यापक विचार-विमर्श नहीं होगा और आम सहमति नहीं बनाई जाएगी, तब तक गोलीबारी का डर बना रहेगा। गन लॉबी को संवेनदशील बनाने की जरूरत है और कांग्रेसी व सीनेटरों को फेडरर एवं राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी का काम करना होगा। तभी कुछ बदलाव संभव होगा।

लालू यादव की बढ़ती मुश्किलें

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की परेशानियां और बढ़ गई हैं। चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाते हुए दो धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनाई है। अब सवाल है कि क्या लालू औपचारिक तौर पर पार्टी की कमान तेजस्वी यादव को सौंप देंगे और क्या तेजस्वी अपने पिता लालू की जगह को भर पाएंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की परेशानियां और बढ़ गई हैं। चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में शनिवार को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाते हुए दो धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की सजा बढ़ जाएगी। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू को विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था। इस समय लालू रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। चारा घोटाले से जुड़े छह मामलों में से अब तक चार में लालू यादव को सजा हो चुकी है। पहले मामल में चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगा, 5 साल की सजा हुई। दूसरे मामले में देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के आरोप में साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। तीसरे मामले में चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।

चारा घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव का जेल जाना देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है, पर यह अप्रत्याशित नहीं है। हमारे देश में बहुत-से राजनीतिकों पर सत्ता में रहते हुए पद का दुरुपयोग करने व भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पर कोई-कोई मामला ही अदालती फैसले तक पहुंच पाता है। चारा घोटाले के मामलों में जांच और न्यायिक कार्यवाही लंबे अरसे से चलती रही है। फिलहाल, लालू की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। चारा घोटाले के दो अन्य मामले जो लंबित हैं उनमें भी लालू प्रसाद आरोपी हैं। फिर, आय से अधिक संपत्ति और धनशोधन के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और आय कर विभाग की जो कार्रवाई लालू परिवार के खिलाफ चल रही है उसकी भी आंच आएगी ही। खासकर बिहार की राजनीति पर इस सब का गहरा असर पड़ेगा। परिवार की जागीर बन चुके राजद के भविष्य पर सवालिया निशान लग चुका है। कांग्रेस ने संकट में लालू के साथ खड़े होने और गठबंधन कायम रखने का इरादा जताया है। इसे मजबूरी का ही निर्णय कहा जा सकता है, कोई नैतिक निर्णय नहीं। भाजपा को एक बार फिर लालू और साथ ही कांग्रेस को घेरने का मौका मिला है।

बहुचर्चित चारा घोटाला लालू की सबसे दुखती रग रहा है। उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान चारे की खरीद काफी बढ़े हुए दाम पर की गई थी। यानी वास्तविक कीमत से ज्यादा भुगतान हुआ। फिर, कई मामलों में तो बिना खरीद के ही भुगतान हो गया। सीबीआई के मुताबिक, यह घोटाला कोई एक हजार करोड़ का था और 1990 से 1997 तक चला। घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू को कुछ बरस पहले जेल जाना पड़ा। उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। पर वे थोड़े ही दिन कैद में रहे। उन्हें जमानत मिल गई और जनवरी में पहला फैसला आने तक वे जमानत पर ही थे। चारा घोटाले के इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर कानूनन पाबंदी लग गई। लेकिन वे अपनी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल का संचालन करते हुए राजनीति में पहले की ही तरह जमे रहे। लालू यादव को 2013 में इसी घोटाले के एक मामले में सजा के बाद सांसद पद छोड़ना पड़ा था और एक तय अवधि तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई थी। उस वक्त माना यही गया था कि लालू यादव की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका बनी रही। वह चुनावी राजनीति से भले ही बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रासंगिकता खत्म नहीं होने दी। बिहार की राजनीति को वह अब तक प्रभावित करते रहे हैं। सबको पता है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका रही है, यह भी कि 2014 में चले मोदी रथ को बिहार में रोकने पर यदि किसी की रणनीति काम आई थी, तो वह लालू प्रसाद यादव ही थे।

अब लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में उनके छोटे पुत्र और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में स्थिति से निपटने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु घोटालों और बेनामी संपत्ति में कार्रवाइयां झेल रहे लालू यादव, उनके पूरे परिवार व राजद की राजनीतिक राह उतनी आसान नहीं दिखती। वैसे, राजद सुप्रीमो की अनुपस्थिति में नीतीश कुमार को खुला राजनीतिक मैदान मिल सकता है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 2019 के मिशन को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में झटका लगने की भी संभावना है। घोटालों और बेनामी संपत्ति के मामलों में कार्यवाइयां झेल रहे लालू यादव के पूरे परिवार के लिए पार्टी के अंदर असंतुष्ट गतिविधियों पर नियंत्रण कर पार्टी को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। हालांकि जब भी इस तरह का संकट लालू यादव और राजद ने झेला है उनकी पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लालू यादव जब भी जेल गए उनके जनाधार में बिखराव नहीं दिखा। चारा घोटाले के तीन और मामलों पर लालू यादव के खिलाफ चल रही सुनवाई और भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद भी उनकी जाति के लोग लालू यादव को अभी भी भगवान मानते हैं। ऐसी संकट की घड़ी में राजद का हर कार्यकर्ता एकजुट रहता आया है, जिसकी वजह से वर्ष 2015 के चुनाव में राजद की बिहार की सत्ता में वापसी हुई थी।

हालांकि, इससे पहले लालू यादव जब भी जेल गए थे, पार्टी की कमान उनकी पत्नी राबड़ी देवी के हाथों में रही थी, जिससे दल के अन्य वरिष्ठ नेताओं के लिए असहज स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। लालू यादव के समकक्ष वरिष्ठ नेताओं को इस बार लालू यादव के पुत्र का नेतृत्व सहज रूप से कितना स्वीकार्य होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। दोनों का राजनीतिक सफर शुरू तो हो चुका है लेकिन लालू के कद तक पहुंचने में अभी उन्हें काफी वक्त लगेगा। फिर भी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पार्टी और लालू यादव के पुत्रों और पूरे परिवार की राजनीतिक राह उतनी आसान नहीं दिखती है।

अब सवाल है कि क्या लालू औपचारिक तौर पर पार्टी की कमान तेजस्वी यादव को सौंप देंगे? सूत्रों के अनुसार अब पार्टी की पसंद और मजबूरी तेजस्वी यादव हैं। वह उपचुनाव का टेस्ट भी पास कर चुके हैं, जिसमें आरजेडी अपने दोनों सीट जीतने में सफल रही थी। हालांकि लालू के सामने अभी तीन तरह की चुनौती है। बड़ी चुनौती सीनियर नेताओं रघुवंश प्रसाद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसों के साथ समीकरण बनाने की है। पिछले दिनों मनोज झा को राज्यसभा भेजकर तेजस्वी ने संदेश दे दिया था कि उनका पार्टी पर नियंत्रण हो चुका है। इसके बाद बड़ी चुनौती अपने कुनबे को बढ़ाने की और गठबंधन की गाड़ी को संवारने की है। अब तक लालू प्रसाद यह काम निभाते रहे हैं। यह स्पेस तेजस्वी के लिए भरना आसान नहीं होगा। अब देखना है कि वे ऐसा कर पाते हैं या नहीं।

मनोज अहिरावत
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

हम उन सैकड़ों हिम्मतवाले अमेरिकियों की तारीफ करते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में गन संस्कृति में बदलाव होगा।

जैक पार्किंसन, प्रवक्ता, व्हाइट हाउस

अमेरिका में गन संस्कृति के बेजा उपयोग के बाद भारत भी इस दिशा में प्रयास करेगा। भारत में भी गन लाइसेंस जारी करने के नियमों को और भी सख्त बनाया जाएगा।

किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री

सत्यार्थ

पौधे की तरह झुकना सीखें

जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में शरशैय्या पर पड़े हुए थे, तब कौरव और पांडव समूह के कई लोग उन के चारों ओर खड़े थे। पितामह ने धीमे स्वर में कहा-अब मैं मृत्यु का वरण करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ ही समय शेष है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके चरणों में बैठते हुए बोले- पितामह, आपके मार्गदर्शन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जब आपका अंत समय करीब है, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें कोई ऐसी उपयोगी शिक्षा दें, जो हमारे आगे के जीवन के लिए लाभदायक हो। भीष्म पितामह ने कहा-आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिसमें जीवन का सार छिपा है। एक दिन समुद्र ने नदी से प्रश्न किया- तुम बड़े-बड़े पेड़ों को तो बहा ले आती हो, लेकिन क्या कारण है कि नन्ही घास, कोमल बेलों और नरम पौधों को तुम अपने साथ नहीं ला पातीं? नदी बोली- जब-जब मेरे पानी का बहाव आता है, तब-तब बेलें, घास के तिनके व नरम पौधे झुक जाते हैं। मगर वृक्ष अपनी कठोरता के कारण झुकने को तैयार नहीं होते। वे सीधे खड़े रहते हैं और उखड़कर बह जाते हैं। वहीं छोटे पौधे इसलिए ज्यों के त्यों बने रहते हैं, क्योंकि उनका विनम्र स्वभाव मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दे देता है, जबकि बड़े पेड़ अहंकार से तन जाते हैं और आप तो यह जानते ही हैं कि विनम्रता के आगे अहंकार परास्त हो ही जाता है। नदी के जवाब से समुद्र संतुष्ट हो गया। यह कहानी सुनाकर पितामह बोले- शायद आप सब भी इस कहानी का सार समझ गए होंगे कि व्यक्ति को सदैव विनम्र रहना चाहिए और विनम्र रहते हुए ही अपने जीवन के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। इतना कहते-कहते भीष्म पितामह ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं।

रेनू सैनी

मुख्य कारोबार समाचार

FY18 के पहले 10 महीनों में सेबी के पास रजिस्टर्ड हुए 1200 नए FPI

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में 1200 से अधिक नए विदेशी निवेशक सेबी के पास पंजीकृत हुए हैं। इसका मुख्य कारण उनका भारतीय पूंजी बाजार में बढ़ता रुझान है। यह जानकारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से मिले हाल ही के आंकड़े से मिली है। बीते वित्त वर्ष में 3500 नए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) बाजार नियामक सेबी के पास पंजीकृत हुए थे। सेबी के डेटा के मुताबिक जनवरी 2018 के अंत तक नियामक की ओर से मंजूरी मिलने वाले एफपीआई की संख्या बढ़कर 9083 हो गई है। यह आंकड़ा मार्च 2017 के अंत में 7807 था। मसलन, इस दौरान 1276 नए निवेशक जुड़े हैं। क्वांटम एडवाइजर्स के हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम एंड ऑलटरनेटिव्स अरविंद चारी ने कहा, 'एफपीआई पंजीकृत की संख्या में तेजी का मुख्य कारण इनका इंडियन इक्विटी, बॉण्ड्स और रियल एस्टेट में बढ़ता रुझान हो सकता है।' इसके साथ ही बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार नियामक सेबी की ओर से उठाए गये कदमों के चलते भारत का आकर्षण बढ़ा है। दिसंबर महीने में सेबी ने ऐसे एफपीआई के प्रवेश नियमों को सरल करने फैसला किया था जो भारतीय बाजार में निवेश करने की रुचि रखते हैं। इस तरह के निवेशकों को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने और पार्टिसिपेटरी नोट (पी-नोट) के माध्यम का इस्तेमाल रोकने की दिशा में किये गये प्रयासों का हिस्सा है।

नीरव मोदी की कंपनी की दिवाला प्रक्रिया में दावा करेगा पीएनबी

नई दिल्ली। नीरव मोदी घोटाले से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी की कंपनी 'फायरस्टार डायमंड' की दिवाला प्रक्रिया में हिस्सा लेने की योजना बनाई है। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी और उसकी कंपनियों पर पीएनबी के साथ 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि बैंक अपने फंसे कर्ज की वसूली के लिये हर संभव विकल्प को तलाश रहा है। इसी कड़ी में बैंक ने फायरस्टार डायमंड इंक की दिवाला प्रक्रिया में शामिल होने की भी योजना बनाई है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिये बैंक कानूनी विशेषज्ञ की सेवायें लेने की प्रक्रिया में है। इस बारे में जल्द ही निर्णय ले लिया जायेगा। इस बारे में पीएनबी से जब बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया। नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड ने पिछले महीने न्यूयार्क की एक अदालत में दिवाला प्रक्रिया के लिये आवेदन किया है। अमेरिका का ट्रस्टी कार्यक्रम दिवाला कानून के तहत कारवाई की देखरेख करता है। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी ने कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से कथित रूप से पंजाब नेशनल बैंक को गारंटी पत्रों के जरिये की गई धोखाधड़ी से 12,968 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। पीएनबी की मुंबई स्थित एक शाखा से वर्ष 2011 से ही नीरव मोदी की समूह कंपनियों को धोखाधड़ी करते हुये गारंटी पत्र जारी किये जाते रहे।

कमजोर बाजार में अधिक मुनाफा देंगे ग्रामीण भारत से संबंधित शेयर

नयी दिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों को अगले कुछ महीने 'संघर्ष' में गुजारने पड़ सकते हैं। हालांकि, इस दौरान ग्रामीण भारत से संबंधित कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन कुछ बेहतर रह सकता है। बैंक आफ अमेरिका मेरिल लिंच (बोफाएमएल) की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल दिसंबर तक सेंसेक्स 32,000 अंक के स्तरके आसपास होगा। यह मौजूदा स्तर से कम है। बोफाएमएल का मानना है कि इस कमजोर प्रदर्शन वाले बाजार में ग्रामीण बाजार से संबंधित शेयर मसलन दोपहिया, सीमेंट और उपभोक्ता सामान कंपनियों का प्रदर्शन कमोबेश बेहतर रहेगा। बोफाएमएल के शोध नोट में कहा गया, ''दिसंबर का हमारा सेंसेक्स का लक्ष्य 32,000 अंक का है जो निचला स्तर है। हालांकि, हमारा अनुमान है कि दोपहिया, सीमेंट और उपभोक्ता सामान क्षेत्र का प्रदर्शन कुछ बेहतर रहेगा।'' रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2019 में आम चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार का खर्च बढ़ेगा। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण खर्च में बढ़ोतरी से ग्रामीण आबादी का जीवनस्तर बेहतर हो सकगा। इससे ग्रामीण खपत और मांग बढ़ेगी। सरकार आवासीय योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीणक्षेत्रों में भारी निवेश कर रही है। इससे ग्रामीण भारत में निर्माण सामग्री की मांग बढ़ेगी।

ONGC ओपीएएल में खरीदेगी गेल की पूरी हिस्सेदारी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सार्वजनिक क्षेत्र की आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन(ओएनजीसी) गुजरात के दहेज में हाल ही में चालू की गई मेगा पेट्रोकेमिकल्स परियोजना का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिये इसमें गेल इंडिया लिमिटेड की पूरी हिस्सेदारी खरीद सकती है। गेल इंडिया ने 2008 में ओएनजीसी पेट्रो-एडीसन लिमिटेड(ओपीएएल) में19 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। कंपनी तब गुजरात के दहेज में मेगा पेट्रोकेमिकल परिसर का निर्माण कर रही थी।

परियोजना का समय बढ़ता चला गया और इसके साथ ही इसकी लागत भी बढ़ती चली गई। परियोजना पर काम 2006 में शुरू हुआ था, लेकिन इसपर समय और लागत बढ़ने के साथ ही गेल का इक्विटी योगदान 996.28 करोड़ रुपये के मूल्य स्तर पर ही रुका रह गया। गेल के इस निवेश की परियोजना की विस्तारित लागत के साथ यदि गणना की जाये तो पहले यह घटकर 17 प्रतिशत रह गई, उसके बाद 15.5 प्रतिशत और अब घटकर 9 प्रतिशत रह गई।

परियोजना से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 'किसी परियोजना में इतनी कम मात्रा में हिस्सेदारी रखने का कोई व्यावसायिक मतलब नहीं है और बेहतर होगा कि ओएनजीसी परियोजना में गेल की हिस्सेदारी खरीद ले।' परियोजना की क्षमता 11 लाख टन की है। जब इस पर काम शुरू हुआ तब इसकी लागत 12,440 करोड़ रुपये आंकी गई थी लेकिन पिछले साल इसके पूरा होने तक इसकी लागत बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

गेल ने 2008 में जब ओपीएएल परियोजना में 19 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी तब परियोजना की लागत 2010 में बढ़कर 19,535 करोड़ रुपये हो गई। कुछ साल बाद जब फिर इसकी समीक्षा की गई तो लागत 2013 में और बढ़कर 21,396 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। अब जबकि परियोजना की लागत 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, गेल का निवेश इसमें9 प्रतिशत रह गया। लागत में होने वाली पूरी वृद्धि का वित्तपोषण ज्यादातर ओएनजीसी ने ही किया।

ब्याज दरों को नहीं बदलेगा RBI, मॉर्गन स्टेनली ने लगाया अनुमान

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारतीय रिजर्व बैंक इस बार की मौद्रिक नीति समिति में ब्याज दरों को यथावत रख सकता है। साथ ही आगामी नीतिगत समीक्षा बैठक में उसकी ओर से अपना रुख तटस्थ रखे जाने की संभावना है। यह जानकारी मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी का मानना है हालांकि भारत की विकास दर बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी फिलहाल शुरुआती चरण में है। ऐसी स्थिति में तटस्थ रुख बरकरार रखने की जरूरत है। मॉर्गन स्टेनली के रिसर्च नोट में कहा गया है कि ग्रोथ और महंगाई के रुख को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरों को यथावत और अपना रुख तटस्थ रख सकती है। केंद्रीय बैंक की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा पांच अप्रैल, 2018 को होनी है। केंद्रीय बैंक ने फरवरी की बैठक में महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए है ब्याज दरों को यथावत रखा था। जनवरी और फरवरी महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति औसतन 4.8 फीसद रही थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक के मार्च तिमाही के 5.1 फीसद के अनुमान से थोड़ कम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रोथ के मोर्चे पर दिसंबर, 2017 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों से यह पता चला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर अग्रसर है। साथ ही देश में नवंबर 2016 में लागू नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से पैदा हुई समस्याएं अब दूर हो रही हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने का खाका तैयार करने वाली समिति अगले हफ्ते सौंपेगी रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दलवई समिति ने कहा है कि किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुना करने के लिए उनकी आय में सालाना 10.4 फीसद के इजाफे की जरूरत है

देश के किसानों की आय दोगुना करने का खाका तैयार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई अंतर-मंत्रालयी समिति अगले महीने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति के अध्यक्ष अशोक दलवई हैं।

दलवई समिति ने अब तक क्या किया: दलवई समिति को अप्रैल 2016 में गठित किया गया था। यह समिति किसानों की 2015-16 के आय स्तर को दोगुना करने के लिए पहले ही 14 खंड लिख चुकी है। इनमें किसानों की आय को सात वर्ष में वास्तविक रूप से दोगुना करने के लिए कई तरीके सुझाए गए हैं। दलवई समिति ने कहा है कि किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुना करने के लिए उनकी आय में सालाना 10.4 फीसद के इजाफे की जरूरत है। दलवई ने कहा, 'अंतिम रिपोर्ट करीब करीब तैयार है। हम इसे अगले महीने सौंप देंगे।' इसके पहले भी पहले से, कुछ पैनल की सिफारिशों को सरकार की ओर से लागू किया जा रह है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर छोटे और सीमांत किसानों को संगठित बाजार ढांचे के साथ जोड़ने के लिए इस साल के आम बजट में 22,000 ग्रामीण हाट के उन्नयन की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि दलवई राष्ट्रीय वर्षाजल सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण(एनआरएए) के सीईओ भी हैं। उन्होंने कहा, हम जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे, इस बीच समिति की कुछ सिफारिशों पर सरकार की तरफ से क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया गया है।

GST रिटर्न की प्रक्रिया होगी आसान, जीरो टैक्स लायबिलिटी वालों को मिलेंगे एक साल में दो मौके

जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में जीएसटी रिटर्न फॉर्म को और आसान बनाने की दिशा में काम कर सकती है।

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत आने वाले ऐसे व्यवसाय जिनकी कर देयता लगातार छह महीनों से जीरो है उन्हें जल्द ही रिटर्न के संबंध में बड़ी राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक ऐसे व्यवसायों को जल्द ही जीएसटी रिटर्न भरने के एक साल में दो मौके मिल सकते हैं। जीएसटी काउंसिल के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा जा चुका है और काउंसिल अपनी अगली बैठक में इस पर निर्णय ले सकती है।

क्या कहते हैं आंकड़े ताजा आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी के अंतर्गत अब तक जितने भी रिटर्न फाइल हुए हैं उनमे से कम से कम 40 फीसद रिटर्न ऐसे रहे हैं जिनमें

व्यवसायों की कर देयता शून्य रही है। अगर काउंसिल अपनी मंजूरी देती है तो जल्द ही ऐसे व्यवसायों के लिए अब हर महीने रिटर्न भरने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इनके लिए नई सरल प्रक्रिया की व्यवस्था की जा सकती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल जिसमें अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं अपनी अगली बैठक में जीएसटी रिटर्न फॉर्म को और आसान बनाने की दिशा में काम कर सकती है। एक अधिकारी के मुताबिक ऐसे करदाता जिनकी कर देयता लगातार छह महीनों से शून्य रही है उन्हें अब छह महीने में एक बार रिटर्न भरने की जरूरत होगी। राजस्व प्राधिकरण की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक रिटर्न की तारीखों में भी बदलाव किया जा सकता है। अब ऐसे कारोबारी जिनका सालाना कारोबार डेढ़ करोड़ रुपए तक का है उन्हें अगले माह की 10 तारीख तक रिटर्न भरनी होगी, जबकि अन्य कारोबारियों को अगले माह की 20 तारीख तक यह काम करना होगा।

FY18 में भारत के तेल आयात बिल में हो सकता है 25 फीसद का इजाफा

अप्रैल-फरवरी की अवधि के दौरान भारत का तेल आयात औसतन 55.74 डॉलर प्रति बैरल का रहा है।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण चालू वित्त वर्ष में, जो कि अगले हफ्ते समाप्त होने जा रहा है, भारत का तेल आयात बिल बढ़कर 87.7 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है। भारत ने वित्त वर्ष 2016-17 में 213.93 मिलियन टन क्रूड ऑयल का निर्यात किया था। इतने तेल के लिए भारत ने 70.196 बिलियन डॉलर यानी 4.7 लाख करोड़ का भुगतान किया था। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भारत का तेल आयात 219.15 मिलियन टन आंका गया है। यानी इस तेल की राशि 87.725 बिलियन डॉलर यानी करीब 5.65 लाख करोड़ रुपए होगी। भारत अपनी तेल संबंधी 80 फीसद जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहता है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 11 महीनों (अप्रैल 2017 से फरवरी 2018) के दौरान देश में 195.7 मिलियन टन क्रूड ऑयल का आयात हुआ है, जो कि करीब 63.5 बिलियन डॉलर के आस-पास बैठता है। भारत जिस बास्केट से कच्चे तेल का आयात करता है उससे अप्रैल-फरवरी की अवधि के दौरान भारत का तेल आयात औसतन 55.74 डॉलर प्रति बैरल का रहा है, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में यह 47.56 बैरल प्रति डॉलर और वित्त वर्ष 2015-16 में 46.17 डॉलर प्रति बैरल रहा है।

ब्रेंट क्रूड ने पार किया 70 का आंकड़ा: साल 2018 में जनवरी महीने के बाद ब्रेंट क्रूड ने एक बार फिर से 70 का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले ब्रेंट क्रूड 31 जनवरी को 70 डॉलर का आंकड़ा पार कर 70.97 के स्तर तक जा पहुंचा था। जानकारों का मानना है कि अगर क्रूड में यह बढ़त जारी रही तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल सकता है।

अडाणी एंटरप्राइजेज ने एनएलसी इंडिया के साथ कोयला खनन समझौता किया

नयी दिल्ली। अडाणी एंटरप्राइजेज ने आज कहा कि उसने तालाबीरा- दो और तीन कोयला ब्लाक के विकास और परिचालन के लिये एनएलसी इंडिया लि. के साथ कोयला खनन समझौता किया है। बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कंपनी ने कहा कि उसकी अनुषंगी तालाबीरा(ओड़िशा) माइनिंग प्राइवेट लि. (टीओएमपीएल) ने एनएलसी इंडिया लि. के साथ कंपनी के साथ कोयला खनन और तालाबीरा दो और तीन कोयला ब्लाक के विकास एवं परिचालन के लिये समझौता किया है।'' टीओएमपीएल तालाबीरा दो और तीन कोयला ब्लाक के लिये सफल बोलीदाता के रूप में सामने आयी। यह बोली पूर्व में नैवेली लिग्नाइट के नाम से चर्चित एनएलसी इंडिया ने आमंत्रित की थी। कोयला मंत्रालय ने ब्लाक के विकास, खनन और ईंधन के निजी उपयोग को लेकर एनएलसी इंडिया को ब्लाक का आबंटन किया था। एनएलसी ने खान के विकास और उसके परिचालन के लिये नवंबर 2017 में निविदा जारी की थी। वहीं उल्टी नीलामी जनवरी में की गयी। इस नीलामी में टीओएमपीएल सफल बोलीदाता के रूप में सामने आयी।

STC के साथ विलय योजना की खबरों से उछले MMTC के शेयर्स

एमएमटीसी के शेयर्स 8.15 फीसद की तेजी के साथ 59.05 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सोमवार के कारोबार में मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एमएमटीसी) के शेयर्स में आठ फीसद तक का उछाल देखा गया है। एमएमटीसी के शेयर्स की कीमतों में यह तेजी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) के साथ विलय की उम्मीद में देखने को मिली है। बीएसई पर एमएमटीसी के शेयर्स 8.15 फीसद की तेजी के साथ 59.05 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है। इसका दिन का उच्चतम स्तर 9.98 फीसद की तेजी के साथ 60.05 और निम्नतम 55.50 का स्तर रहा है। वहीं, इसका 52 हफ्तों का उच्चतम 101.60 का स्तर और निम्नतम 45.50 का स्तर रहा है। वहीं, एनएसई पर यह 8.34 फीसद की तेजी के साथ 59.10 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है।

इसी तरह एसटीसी के शेयर्स ने 4.98 फीसद की तेजी के साथ 142.15 का स्तर छुआ। लेकिन यह 1.29 फीसद की तेजी के साथ 137.15 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है। इसका दिन का उच्चतम 142.15 और निम्नतम 135.05 का स्तर रहा है। एसटीसी का 52 हफ्तों का उच्चतम 299 का स्तर और निम्नतम 135 का स्तर रहा है। वहीं दूसरी ओर एनएसई पर एसटीसी 1.10 फीसद की बढ़त के साथ 137.55 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एमएमटीसी) तथा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) की विलय योजना पर काम चल रहा है। प्रभु ने कहा, 'दोनों कंपनियों के विलय पर काम पहले से ही जारी है, क्योंकि दुर्भाग्य से एसटीसी बीमार कंपनी की श्रेणी में आ गई है।'मंत्रलय ने कुछ समय पहले अपने अधीन आने वाली तीनों कंपनियों की नई संरचना के लिए अध्ययन का काम शुरू किया था। गौरतलब है कि एसटीसी, प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीईसी) तथा एमएमटीसी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती हैं।

आधार को बीमा पालिसी के साथ जोड़ने की समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने विभिन्न बीमा पालिसियों के साथ 12 अंकों का आधार नंबर जोड़ने के लिये समयसीमा को उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने तक बढ़ा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में दायर रिट याचिका को लेकर 13 मार्च को दिये आदेश में विभिन्न योजनाओं के साथ आधार नंबर जोड़ने की समयसीमा को इस संबंध में अंतिम सुनवाई होने और फैसला आने तक के लिये बढ़ा दिया है।

उच्चतम न्यायालय के इसी आदेश को देखते हुये इरडा ने बीमा पालिसियों के साथ आधार संख्या जोड़े जाने की समयसीमा को 31 मार्च से आगे अनिश्चित काल तक के लिये बढ़ा दिया है। बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों को जारी किये गये एक सर्कुलर में कहा, ''मौजूदा बीमा पालिसियों के मामले में इनके साथ आधार संख्या को जोड़ने की अंतिम तिथि इस मामले की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई पूरी होने और फैसला सुनाये जाने तक के लिये बढ़ाई जाती है।'' जहां तक नई बीमा पालिसी की बात है, बीमा पॉलिसी खरीदार को उसका खाता शुरू होने से लेकर छह माह के भीतर अपनी आधार संख्या, पैन अथवा फार्म 60 को बीमा कंपनी में जमा कराना होगा।

बीमा नियामक ने कहा है, ''आधार संख्या नहीं होने की स्थिति में ग्राहक को मनी-लांड्रिंग रोधी (रिकार्ड का रखरखाव) नियम 2005 में दर्ज किये गये किसी भी वैध दस्तावेज को सौंपा जा सकता है।'' नियमों के तहत प्रवासी भारतीय पालिसीधारक को आधार नंबर नहीं होने की वजह से अपनी पॉलिसी लौटाने की आवश्यकता नहीं है। आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में प्रवासी भारतीय, भारतीय मूल का व्यक्ति, विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय मनी लांड्रिंग रोधी कानून में बताये गये किसी भी वैध दस्तावेज को जमा करा सकते हैं।

2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा भारतः वित्त मंत्रालय

भारत की जीडीपी 2.5 ट्रिलियन डॉलर है जो कि दुनिया की छठीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करने की दिशा में ही बढ़ रहा है और वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के पांच ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना है। वहीं वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार महंगाई दर को आरबीआई की ओर से तय किये गए लक्ष्य से आगे नहीं जाने देना चाहती है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सीआईआई ग्लोबल इंडस्ट्री एसोसिएशन्स समिट में कहा, 'देश सात से आठ फीसद के ग्रोथ रेट को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही स्टार्टअप, एमएसएमई और बुनियादी निवेश पर फोकस करते हुए वह विकास दर में बढ़ोतरी प्राप्त कर सकता है।'

उन्होंने बताया, 'मुझे लगता है कि यह उम्मीद करना तर्कसंगत है कि अगर अर्थव्यवस्था वस्तु एवं सेवा के उत्पादन पर फोकस करेगी और अगले सात से आठ वर्षों के लिए मांग सृजित करेगी तो हम वर्ष 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। यह समझदारी से तय किया गया लक्ष्य है।' वर्तमान में वैल्यू के आधार पर भारत की जीडीपी 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है। यह दुनिया की छठीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। महंगाई के संदर्भ में सुभाष ने बताया कि इसका प्रक्षेप पथ (ट्रैजेक्टरी) आरबीआई के चार फीसद, दो फीसद ऊपर या नीचे, के लक्ष्य के भीतर है। आपको बता दें कि फरवरी में थोक महंगाई दर गिरकर सात महीने के निचले स्तर 2.48 फीसद पर और खुदरा महंगाई दर चार महीने के निचले स्तर 4.44 फीसद पर आ गई है।

सब को जोड रहा है निरंकारी मिशन, पलसाना में हुआ सत्संग

सूरत। संत निरंकारी मिशन सार्वभौमिक आध्यात्मिक मंच है जहां हर धर्म व जाति के लोग एक ही छत के नीचे मिल बैठे हैं। उक्त उदगार निरंकारी प्रचारक संत श्री विनोदजी ने कल ब्राह्मण फलिया स्थित पलसाना में आयोजित सत्संग में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संत निरंकारी मिशन ब्रह्मज्ञान द्वारा हर इंसान को ईश्वर से जोड रहा है, ईश्वर को अलग-अलग नाम के कारण ही इंसान बता हुआ है। जबकि एक ईश्वर के साथ ोड कर ही हम सब एक हो सकते हैं। निरंकारी संत ने कहा कि सदगुरू माता सविन्दर हरदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में निरंकारी मिशन ब्रह्मज्ञान देकर हर इंसान से भ्रम भ्रान्ति दूर कर रहा है। ब्रह्मज्ञान संसय को दूर करता है, प्रभु के प्रति विश्वास बढता है। ब्रह्मज्ञान प्रभु की नजदीकियां का अहसास कराता है। अत: ब्रह्मज्ञान हर मानव के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चांद पर मंगल पर पहुंचने वाले को धरती पर मंगलमय जीवन व्यतीत करना है तो प्रेरक मार्गदर्शक की शरण में आना होगा। वर्तमान में सदुरूमाता सविन्दर हरदेव जी महाराज इंसान को ब्रह्मज्ञान प्रदान कर सब के जीवन में मंगलकारी बना रहे हैं। स्थानिय सरपंच श्री प्रवीण भाई आहीर ने सत्संग में भाग लिया और सरपंच जी का निरंकारी प्रचारक ने बुके देकर स्वागत किया।

प्राइमस से झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत

सूरत। लिंबायत के नीलगीरी सर्कल के समीप आने वाले रतन चौक की रहने वाली एक महिला गत 22 मार्च को खाना बनाते समय प्राइमस भभकने से गंभीर रूप से झुलस गई थी। जिसको इलाज के लिए स्मीमेर अस्पताल में भर्ती किया गया जहां पर गत रोज उसकी मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लिंबायत के नीलगीरी सर्कल के पास रतन चौक स्थित जवाहर नगर घर नं. 354 में रहने वाले संदीप यादव की पत्नी पूनमबेन (26 वर्ष) गत 22 मार्च को खाना बना रही थी। उसी समय अचानक ही प्राइमस भभकने से पूनम के शरीर का काफी हिस्सा झुलस जाने से गंभीर हालत में इलाज लिए स्मीमेर अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां पर रविवार को पूनम की मौत हो गई। पुलिस आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करके जांच कर रही है।

विकास कार्यों के विधायकों की ग्रांट में 50 लाख की वृद्धि : नितिन पटेल

गांधीनगर। उप मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मंत्र के तहत राज्य के नागरिकों को सिलसिलेवार सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने को सरकार प्रतिबद्ध है। विधानसभा में आज विनियोग विधेयक 2018 पेश करते हुए नितिन पटेल ने राज्य की विकास यात्रा गति प्रदान करने के लिए विधायकों की ग्रांट रु. 1 करोड़ से बढ़ाकर रु. 1.50 करोड़ कर दी गई है। ताकि वे अपने निवार्चन क्षेत्रों के विकास कार्यों को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 बजटीय प्रावधान के मुकाबले रु. 11487 करोड़ की वृद्धि निर्दिष्ट की गई है। जिसमें नई योजनाओं के जरिए राज्य की विकास यात्रा को गति प्रदान करने के लिए बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन किया गया है। कृषि में मूल्यवृद्धि, किसान कल्याण, युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर, सिंचाई सुविधा, गुणवत्तायुक्त जलापूर्ति, गरीबों के लिए सस्ते आवास, पोषक आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ढांचागत सुविधाओं को प्राथमिकता देकर संसाधनों का समायोजन बजट में किया गया है। राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के कारण वेतनभत्ते और पैंशन खर्च में वृद्धि होने के बावजूद वर्ष 2018-19 के बजट में रु. 783 करोड़ समेत रु. 5988 करोड़ के राजस्व अधिशेष वाली सातवां बजट पेश किया गया है। नितिन पटेल ने कहा कि राज्य के नागरिकों के लिए पेयजल का आयोजन किया गया है और पर्याप्त जलराशि उपलब्ध है। नर्मदा योजना के बाइपास टनल द्वारा पानी लेकर नागरिकों को उपलब्ध करवायाजा रहा है। मध्य प्रदेश से अतिरिक्त पानी छोड़ने की पेशकश के बाद अब वहां से छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीमा की रकम जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 80 लाख किसानों के 969 दावे मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले दफा राज्य में मूंगफली का विपुल उत्पादन हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदने की मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत रु. 3740 करोड़ के खर्च से 8.32 लाख मेट्रिक टन मूंगफली खरीदी गई, जिसका चार लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के विकास पर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। आदिवासी क्षेत्रों के 5627 गांवों में से 5600 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। 27 गांव में से 12 गांवों के डूब में जाने से वहां कोई रहता नहीं है। शेष गांवों में भी जल्द काम पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन अधिकार नियम के तहत आदवासियों को जंगल की जमीन का अधिकार देने के मामले में गुजरात सबसे आगे है। 28 फरवरी 2018 तक 18 2896 व्यक्तिगत और 7187 सामूहिक दावे किएगएहैं। जिसमें से 84211 व्यक्तिगत और 4659 सामूहिक दावों को मंजूर कर आदिवासियों को अधिकार दिया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केडर में 70000 युवकों को सरकारी नौकरी दी है और आगामी समय में और भर्ती की जाएंगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर मानव उपलब्ध हो इसके लिए आगामी वर्ष नई 25 जीआईडीसी शुरू करने का राज्य सरकार ने फैसला किया है।

उधना से निकली भव्य श्रीराम शोभा यात्रा

नवदुर्गा महिला मंडल और हिंदू वाहिनी ने किया विविध आयोजन

सूरत। शहर में बीते रविवार को उधना इलाके से हिंदू वाहिनी और नव दुर्गा महिला मंडल की कार्यकर्ताओं ने श्रीराम जन्मोत्सव मनाने के साथ विहंगम श्रीराम शोभा यात्रा निकाली। हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता उधना इलाके से प्रमोद सिंह की अध्यक्षता में विशाल बाइल जुलुस निकाला। जुलुस उधना से सूरत रेलवे स्टेशन, भागल चार रास्ते से होते हुए नानपुरा इलाके में पहुंचक र सम्पन्न हुई। इस बाइल रैली में हिंदू वाहिनी के प्रमोद सिंह यादव, बजरंग भाई खंडेलवाल, हेमंत देसाई, कमलेश सिंह, विजय छेत्रवाडी, राजेश खत्री, अमृत शर्मा, ओमप्रकाश, मनोहर सिंह सहित काफी तादाद में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता शामिल थे। वहीं उधना इलाके से नव दुर्गा महिला मंडल अध्यक्ष रेखा ठाकुर की अगुवाई में रविवार को श्रीराम जन्मोत्सव को मनाया गया। इस अवसर पर महिला मंडल की कार्यकर्ताओं ने श्रीराम जी की विशाल शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा उधना से शुरू होकर चीकूवाडी से होते हुए पियूष प्वाइंट स्थित श्रीराम मेंदिर परिसर में पहुंचकर सम्पन्न हुई। शोभायात्रा में रेखा ठाकुर, ताराबेन मिश्रा, जयश्री बेन,संगीता तिवारी, चिंकी अनुसुईया बेन, बिंदु शर्मा, बबिता बेन सहित काफी तादाद में महिला कार्यकर्ता शामिल थी।

जिला की तीन नगरपालिकाओं में चीफ ऑफिसरों की भर्ती के लिए मंगवाई अर्जी

सूरत। सूरत जिला की कडोदरा, मांडवी और बारडोली नगर पालिकाओं में 11 मास के करार पर आधारित चीफ ऑफिसरों की जगह के लिए पसंदगी समिति द्वारा निवृत्त मामलतदार तथा निवृत्त नायब मामलदार के पास से अर्जियां मंगाई हैं।

भर्ती प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा निश्चित किए गए शर्तों के अधीन होगी। निवृत्त नायब मामलदार, निवृत्त मामलदार तथा विवृत्त नायब कलेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच चालू नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण व्यक्तिगत होने चाहिए। 62 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। सेवाएं संतोषजनक न रही तो कलेक्टर और सरकार द्वारा 11 माह पहले करार के आधार पर चयन को रद्द किया जा सकेगा साथ ही उन्हें राज्य के अन्य नगरपालिकाओं में भी बदली किया जा सकेगा।

पढ़ाई के तनाव में जहर पीकर आत्महत्या

सूरत। कापोद्रा के योगी चौक के समीप रहने वाले एक 22 वर्षीय छात्र ने पढ़ाई को लेकर हमेशा तनाव में रहते हुए जहरीली दवा पी लेने से मौत हो गई। कापोद्रा पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कापोद्रा के योगी चौक श्यामधाम सोसाइटी घर नं. 28 में रहने वाले सुरेश राशडिया के पुत्र विवेकभाई रासडिया (22 वर्ष) पिछले काफी समय से पढ़ाई को लेकर तनाव में रहते थे।

सूरत। मॉडल टॉउन के समीप सब्जी मार्केट में रत्नागिरी हापुस का बोलबाला तो है। परन्तु इस वर्ष व्यापारी मायूस नजर आ रहे है। रत्नागिरी हापूस बेचता व्यापारी तस्वीर में द्रश्यमान है।

बक्षीपंच समाज के लिए समाज शिक्षण शिविर का आयोजन

सूरत। विकसती जाति कल्याण विभाग एवं श्री गुर्जर क्षत्रिय समाज के संयुक्त उपक्रम में गुजरात पछात वर्ग विकास निगम के अध्यक्ष नरेन्द्र भाई सोलंकी की अध्यक्षता में समाज शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

रांदेर के श्री गुर्जर क्षत्रिय समाज भवन में आयोजित इस शिविर में बक्षीपंच समाज के जरूरतमंदों को विकसती जाति कल्याण खाता की योजनाओं के अन्तर्गत पचास लाख से भी अधिक साधन सहायता इनायत किया गया। इसमें बक्षीपंच के छह विद्यार्थियों को 40.50 लाख की विदेश में पढाई के लिए लोन सहायता, सात फेरा समूह लग्न योजना के तहत 37 लाभार्थियों को 3.70 लाख, कुंवर बाईनुं मामेरू योजना के तहत 36 बेटियों को 3.60 लाख तथा कक्षा एक से 12 में पढने वाले जिला के मेधावी छात्रों को 51000 रूपये का ईनाम वितरण किया गया। इस अवसर पर निगम के अध्यक्ष सोलंकी ने बक्षीपंच समाज की 146 जातियेां को एकसूत्र में बांध कर सरकार द्वारा दी जाने वाली विविध योजनाओं का लाभ लेने के लिए आह्वान किया। बक्षीपंच समाज के तमाम वर्गों के लोगों को योजनाओं को लाभ देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

अंत्योदय के कल्याण भाव को सेवा का लक्ष्य बनाएं: मुख्यमंत्री

भर्ती परीक्षा में चयनित १०५४ नौजवानों को मुख्यमंत्री ने दिए नियुक्ति पत्र

गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य सरकार की सेवा में शामिल हो रहे नवनियुक्त युवा कर्मियों से आह्वान किया कि वे मानवीय संवेदना के साथ अंतिम आदमी-अंत्योदय के कल्याण भाव को सेवा का लक्ष्य बनाकर सेवारत रहें। वे गांधीनगर में सोमवार को गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा वरिष्ठ लिपिक, म्युनिसिपल लेखाकार एवं उप लेखाकार के रूप में चयनित १०५४ युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। रूपाणी ने इन नौजवानों का 'टीम गुजरात' में स्वागत करते हुए कहा कि गुजरात सरकार के कर्मयोगी और सुशासन की जो छवि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में एक मॉडल के रूप में स्थापित की है, उसे वे अपने कर्तृत्व भाव से और भी उजागर करें। उन्होंने साफ कहा कि यह सरकार पारदर्शी और संवेदनशील है, जिसकी अनुभूति सामान्य से सामान्य नागरिक को भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सेवा के साढ़े चार लाख से अधिक कर्मचारी, मंत्रिपरिषद और पदाधिकारियों सहित समग्र सरकार पीड़ित, शोषित, वंचित और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को सहायक बनने के लक्ष्य के साथ कार्यरत है। युवाओं से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि, 'अपना काम और समस्या लेकर आपके पास आने वाले याचक में स्वयं को रखकर उनकी समस्या का सुचारु निवारण करने का जवाबदेह दायित्व आपको भी निभाना है'। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार के सचिवालय से लेकर तहसील स्तर तक के कर्मयोगियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के लिए बायोमीट्रिक्स और डैश बोर्ड जैसी आईटी टेक्नोलॉजी आधारित पैरामीटर्स विकसित करने की मंशा जतायी।

इस संदर्भ में उन्होंने नवनियुक्त युवा उम्मीदवारों से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी मिलने पर स्थिरता और सुरक्षा का भाव जरूर आता है, लेकिन आप कार्य को टालने का भाव कभी पनपने नहीं देना। टेक्नोसेवी युवा पीढ़ी अब बड़े पैमाने पर राज्य सरकार की सेवा से जुड़ रही है, ऐसे में उनके ज्ञान-कौशल से प्रशासनिक मोड को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प करने की उन्होंने युवाओं को सीख दी।

रूपाणी ने कहा कि पिछले दो वर्ष में राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में पारदर्शी तरीके से एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर कसौटी पर खरे उतरे ८० हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं।

मौसम पर निर्भर होते हैं रत्नागिरी हाफुस व अन्य आम के फल

सूरत। गुजरात में सबसे अधिक बिकने वाली केसर केरी घर घर की पसंद है। आम की इन दिनों आवक सामान्य है। कोंकड़ और देवगढ़ रत्नागिरी आम बाजार में धड्ड्ले से बिक रहे है। हापुस आम की आवक सूरत के स्थानीय सब्जी मार्केट में बिना हिचकिचाहट लोग खरीदी कर रहे है। हापुस आम मीठा होता है ,उसमे तुरापन या खटाश होती। आम के फूल दिसंबर माह में ही लगने शुरू हो जाते है। फरवरी माह में आम बाजार में आते है। कोकण हापुस इन दिनों बाजार में बिक रही है ,देशावर में आम की आवक अधिक है ,जबकि सूरत के कृषि मंडी में थोकभाव से आम आने लग गए है। कोंकण के हापुस आमो की सर्वश्रेष्ठ किस्म देने वाली रत्नागिरी का देवगढ़ तहसील आमो का राजा है। हापुस रत्नागिरी बाजार में आठसो रूपये दर्जन के भाव से बिक रही है ,नतीजतन ,पंद्रह दिनों से बाजार में बिकने वाली रत्नागिरी हापुस का दाम करीब हजार रूपये के आसपास था ,इन दिनों दामों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आठसो रूपये दर्जन से बिकने वाली हापुस आमतौर से बाजार में प्रचुर मात्रा उपलब्ध नहीं है।

वैसे तो रत्नागिरी आम सभी खरीद सकते ,है लेकिन यह धनाढ्य लोगो की पहली पसंदगी है। मौसम प्रतिकूल नहीं होता है ,तो आम की फसल किसानो के लिए बेहतर साबित हो सकती है। कोंकण क्षेत्र के हापुस सर्वश्रेष्ठ होते है। दरअसल, कोंकण के बाद दक्षणि अफ्रीका से भी हापुस को आयात किया जाता है। इसके लिए सरकार की स्वकृति भी मांगी गई थी। कर्णाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हापुस आते है। लेकिन कोंकण हापुस के दाम से आधा ही रहता है। तीन सौ चार सौ और पांचसो रुपये दर्जन हापुस अन्य राज्यों में सप्लाई होते है। मॉडल टाउन के समीप कृषि मंडी सब्जी मार्केट में जय अंबे फ्रूट सेंटर के मालिक सुभाष जयसवाल ने संवाददाता को बताया कि रत्नागिरी हापुस 15 दिनों से बाजार में है ,लेकिन दामों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। इस फल की नहीं है आवक अच्छी है ,लेकिन अभी अगले दस दिनों में आम बाजार में आने लग जायेंगे । सलमान ने बताया की रत्नागिरी हापुस का दाम स्थिर है ,लेकिन इस वर्ष बाजार बिलकुल ठंडा चल रहा है। इसका हमें कोई पता है, लेकिन हरवर्ष हम इस समय अच्छा व्यापार कर लेते थे।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **Tc.No. : GUJHIN00722**, E-mail: krantisamay@gmail.com